चिंता मत कर
वो भी रोयेगा
जो आज तुझे रूला
रहा है।
– अज्ञात

जीवन में क्रांतिकारी बदलाव

मोदी ने कहा कि भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक रोडमैप तैयार करना होगा जिसमें गरीबी उन्मूलन और पानी से जुड़े मुद्दों को खासतौर से तवज्जो देने की जरूरत है।

कोमल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरशाही से सीधा संवाद करने और उसे गतिशील बनाए रखने की नीति को अपने दूसरे कार्यकाल में भी जारी रखा है। उन्होंने साफ कहा कि आप सभी ने जिस कड़ी मेहनत से काम पूरा किया, उसी का परिणाम था कि चुनाव में हमारे पक्ष में सकारात्मक वोट पड़े। उन्होंने अधिकारियों को अपने–अपने मंत्रालय के लिए पांच साल की योजना तैयार करने को कहा और आश्वस्त किया कि योजनाओं को सौ दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाएगी।

मोदी ने कहा कि आप सभी अपने आपको प्रधानमंत्री समझें और देश, समाज और खासकर गरीबों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए काम करें। अगर ऐसा करते हुए आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह मेरी गलती होगी। इससे पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने नौकरशाहों को इस तरह से विश्वास दिलाया हो। मोदी ने कहा कि भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक रोडमैप तैयार करना होगा जिसमें गरीबी उन्मूलन और पानी से जुड़े मुद्दों को खासतौर से तवज्जो देने की जरूरत है। नौकरशाहों में इस तरह उत्साह भरना और काम के लिए प्रेरित करना नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की विशेषता रही है।

उनके पहले कार्यकाल के दौरान पीएमओ ने प्रशासन में सुधार के लिए विभिन्न विषयों पर सचिवों के आठ समूहों का गठन किया था। प्रधानमंत्री हर महीने विभिन्न राज्यों के सचिवों के साथ भी बातचीत करते रहे हैं जिसके सकारात्मक परिणाम निकले। सरकार की कई गरीब समर्थक योजनाएं जमीन पर बेहतर ढंग से उतरीं और जरूरतमंदों तक पहुंचीं। नौकरशाही को सक्रिय रखने के साथ उसके स्वरूप में बदलाव भी मोदी सरकार का अजेंडा रहा है। सरकार ने लैटरल एंट्री के जरिए अपने विभिन्न मंत्रालयों में 9 प्रफेशनल्स को संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया। इनमें से ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर से हैं। इन्होंने कुछ ही महीने पहले कार्यभार संभाला है। सरकार इस प्रयोग को और विस्तार देने जा रही है। वह संयुक्त सचिव स्तर के चालीस फीसदी पदों पर गैर आईएसएस अफसरों को रखना चाहती है।

अभी तक सभी अफसरों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के जरिए होती रही है, लेकिन सरकार अब नीति आयोग के जरिए भी अधि कारियों को नियुक्त करना चाहती है। सरकार का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने–अपने फील्ड में सामान्य आईएएस की तुलना में बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में यह प्रयोग काफी सफल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोदी सरकार भारतीय नौकरशाही के ढांचे और माइंडसेट में बदलाव लाएगी जिसका लाभ देश के हर वर्ग को मिलेगा।

वास्तव में आत्मा हैं

धर्म-दर्शन

राजिन्दर सिंह जी महाराज। शरीर केवल आत्मा के ऊपर चढ़ा आवरण है। अध्यात्म के द्वारा हम अपने सच्चे आंतरिक रूप को पहचान सकते हैं। ध्यान–अभ्यास और प्रार्थना की मदद से हम अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं ताकि हम जान सकें कि हम वास्तव में हैं कौन।

हममें से कइयों के पास कारें हैं। कई बार कार खघ्राब हो जाती है और उसे मरम्मत के लिए भेजना पड़ता है। इससे हमें चाहे थोड़े दिनों के लिए असुविधा हो और हमें किराये पर कार लेनी पड़े या हमारे परिवार के किसी सदस्य या मित्र को हमें अपनी कार में यहाँ–वहाँ घुमाना पड़े, लेकिन हमें ऐसा तो नहीं लगने लगता मानो हमारी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। हम जानते हैं कि कार तो सिर्फ एक भौतिक साधन है जिसका इस्तेमाल हम अपने शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते है।

संपादकीय

राजनीति और न्याय

जम्मू–कश्मीर के कठुआ जिले में एक आठ वर्षीय बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में न्याय तो हो गया, लेकिन इस प्रकरण में लहूलुहान हुई इंसानियत को क्या नई जिंदगी मिल पाएगी? पठानकोट की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कठुआ कांड में छह लोगों को दोषी करार दिया। सातवें आरोपी, यानी मुख्य आरोपी सांझीराम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है। मामले में हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को भी दोषी ठहराया गया है, जिन पर सांझीराम से चार लाख रुपये लेकर सबूत मिटाने का आरोप था। एक धार्मिक–राजनीतिक संगठन ने खुलेआम अभियुक्तों के पक्ष में अभियान छेड़कर इसे हिंदू–मुस्लिम का मामला बना दिया। हद तो तब हुई जब तत्कालीन पीडीपी–बीजेपी सरकार के दो मंत्री भी इसमें कूद पड़े, जिनकी बाद में सरकार से छुट्टी करनी पड़ी। अंततरू 7 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने यह केस कठुआ से हटाकर पंजाब के पठानकोट में स्थानांतरित कर दिया, जहां बंद कमरे में मामले की सुनवाई बीते 3 जून को पूरी हुई। हमारे दिलों का बंटवारा आज इस कदर हो चुका है कि बलात्कार और हत्या जैसी जघन्य घटना में भी हम पीड़ित और अभियुक्त का धर्म और जाति देखने लगे हैं। संवेदना हमारी इस कदर मर गई है कि एक मृतक और हत्यारे की सामाजिक पहचान देखकर तय करते हैं कि किसके साथ खड़ा होना चाहिए। यह बीमारी अगर जल्दी दूर नहीं हुई तो कानून–व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं के लिए ठीक से काम करना असंभव हो जाएगा। ऐसी घटनाओं पर जजमेंटल होने से अच्छा है, हम सिस्टम को अपना काम करने दें और जरूरी लगे तो उसे अधिक सक्षम और तत्पर बनाने के लिए आवाज उठाएं।

भारतीय अर्थव्यवस्था आज कुछ उसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है जो 21वीं सदी के इन दो दशकों में सबसे कठिन मानी जाती रही हैं।

आर्थिक विकास के मोर्चे पर

नवीन

रिजर्व बैंक ने साल की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति में ब्याज दरें घटाने से तो मना कर ही दिया, इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी 6.1 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी पर ला दिया। इससे पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार पांच बार रीपो रेट में कटौती की थी। रीपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जीडीपी ग्रोथ के ताजा आंकड़े बता रहे थे कि जुलाई–सितंबर तिमाही में यह 4.5 फीसदी पर खिसक आई है, जो पिछले छह साल का सबसे निचला स्तर है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही थी कि रिजर्व बैंक रीपो रेट में थोड़ी और कमी लाकर आर्थिक गतिविधियां तेज करने में सरकार का हाथ बंटा सकता है। लेकिन एक तो पिछली पांच कटौतियां आर्थिक विकास के मोर्चे पर कुछ खास फायदा नहीं दे सकीं, दूसरे, लगातार कटौतियों के बाद अब रिजर्व बैंक के पास पीछे जाने की गुंजाइश भी नहीं रह गई थी। खुदरा महंगाई दर का अनुमान उसने 4.7 से 5.1 प्रतिशत के बीच रखा है। ऐसे में रीपो रेट को मौजूदा 5.15 प्रतिशत से नीचे लाना नकारात्मक ब्याज दरों के खतरनाक दायरे में प्रवेश करने

जैसा था। हालांकि आगे महंगाई नीचे जाने की स्थिति में आरबीआई ने अपने विकल्प खुले रखे हैं। केंद्रीय बैंक ने उम्मीद जताई है कि सरकार द्वारा पहले ही उठाए जा चुके कुछ कदमों के चलते अगली तिमाही में बेहतर नतीजे देखे जा सकते हैं, लेकिन उसके वक्तव्य में आए ब्यौरे अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति की ओर ही इशारा करते हैं।

ग्रोथ रेट बेशक, इससे पहले भी पांच फीसदी से नीचे गई है। इस लिहाज से मौजूदा स्थितियों को अभूतपूर्व नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज कुछ उसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है जो 21वीं सदी के इन दो दशकों में सबसे कठिन मानी जाती रही हैं। 2008–09 जैसी वैश्विक मंदी आज नहीं है और 2012–13 जैसी पॉलिसी पैरालिसिस वाली स्थिति भी नहीं है। लेकिन पिछले दोनों मौकों पर सरकारें संकट से निपटने के लिए हाथ–पांव मारती नजर आती थीं, जबकि इस बार सरकार की कोशिश संकट जैसी धारणा को ही सिरे से खारिज करने की रही है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी रिजर्व बैंक के इस बयान के बाद सारी जय–क्षय सरकार पर ही आ गई है।

ग्रोथ के चार प्रमुख कारकों में से तीन में फिलहाल कोई हलचल नहीं है। न विदेशी निवेश की कोई लहर करीब है, न निजी निवेश में कोई उत्साह देखा जा रहा है, न ही उपभोक्ता खर्च में किसी बड़ी बढ़त के आसार हैं। ऐसे में सारी उम्मीदें सरकारी निवेश पर ही टिकी हैं। यह सरकार के कौशल का इम्तहान है। मंत्रियों की कोशिश छोटे–छोटे मामलों में भी आर्थिक सक्रियता की गुंजाइश बनाने की होनी चाहिए, बयान बहादुरी का वक्त जा चुका है। रिजर्व बैंक ने सुझाया है कि लंबित परियोजनाओं के रास्ते की अड़चनें दूर करके इन्हें जल्द से जल्द चालू करना अभी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए।

सूडोकु नवताल-5189

सरल

	7	9	4	2		6		3
	6		8		7		2	
4	1				3	5	8	
	9	8	3					
7		4		5		8		1
					9	7	3	
	8	5	7				4	6
	2		9		1		5	
3		1		6	8	9	7	

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5188 का हल

8	9	5	1	3	7	2	4	6
7	3	2	6	5	4	1	8	9
1	6	4	8	9	2	7	5	3
5	7	3	4	2	9	6	1	8
4	2	8	5	6	1	3	9	7
6	1	9	3	7	8	5	2	4
3	5	1	9	4	6	8	7	2
2	4	6	7	8	5	9	3	1
9	8	7	2	1	3	4	6	5

अपना ब्लॉग

अयोध्या को लेकर फिक्रमंद नहीं हैं मुसलमान

युसुफ किरमानी। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद इसके इर्द–गिर्द बिछी राजनीतिक बिसात सिमटने का नाम नहीं ले रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा–ए–हिंद ने कहा है कि 99 फीसदी मुसलमान चाहते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाना था, जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम संभालेगा। 25 दिन से ज्यादा हो चुका है लेकिन ट्रस्ट नहीं बना। इस ट्रस्ट में जगह पाने के लिए तमाम साध ु–संतों के अखाड़े और कई स्वयंभू बाबा अलग तरह की राजनीति में व्यस्त हैं। यह भी सही है कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में तटस्थ चल रहे लोगों के गले नहीं उतरा और उसके विरोधाभासों को लेकर चर्चा जारी है। लेकिन यहां जेरे–बहस 99 फीसदी मुसलमानों के नाम पर लाई गई याचिका है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के 27 साल पूरे होने से ठीक पहले दायर की गई है।